

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 22 मार्च, 2017

विषय:- महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून में नवनिर्मित एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्रैक में दर्शक दीर्घा (पवेलियन-3000 क्षमता) के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1259/ब0पत्रा0/2016-17/दे0दून, दिनांक 20 फरवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-352/VI/2016-21(2)/2012, दिनांक 27 अप्रैल, 2016, शासनादेश संख्या-290/VI-2/2015-21(2)/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015, शासनादेश संख्या-159/VI/2016-21(2)/2012, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-625/VI/2016-21(2)/2012, दिनांक 16 अगस्त, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर, देहरादून में नवनिर्मित एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्रैक में दर्शक दीर्घा (पवेलियन-3000 क्षमता) के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत आगणन ₹998.42 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा संस्तुत आगणन ₹ 985.82 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 954.47 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 31.35 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 441.73 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 200.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2015-16 में तृतीय किस्त के रूप में ₹ 66.67 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ किस्त के रूप में ₹ 133.33 लाख इस प्रकार ₹ 841.73 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 144.09 लाख के सापेक्ष बालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में चतुर्थ अन्तिम किस्त के रूप में ₹ 144.09 लाख (एक करोड़ चवालीस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या-414/XXVII(7)/2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-594/XXVII(7)/2010, दिनांक 09 जून, 2010 के अनुसार MOU हस्ताक्षरित कर समय सारिणी के अनुरूप उक्तानुसार समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायें। निर्माण कार्य का गहन अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय। भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलंब या अन्य किसी दशा में आगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।



- 4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5- कार्य करने से पूर्व से समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- 7- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 9- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यों से इतर कार्यों/उपकरणों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 10- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
- 11- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय। कार्य के गुणवत्तापरीक्षण के सम्बन्ध में नियोजन विभाग से समन्वय का तदनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज से वहन किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-11-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-26-38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-346(P)/XXVII(3)/2016-17, दिनांक 21 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-SI 70311 037p दिनांक : 22 मार्च, 2017

मयदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 123 /VI/2017-21(2)/2012, तपदिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
8. जिला कीड़ाधिकारी, देहरादून।
9. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।